



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1124]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/वैशाख 1, 1939

No. 1124]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/VAISAKHA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का.आ. 1267(अ).—भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 का अनुसरण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

- (क) सरकारी प्रतिभूतियां;
- (ख) प्रतिभूतियां, जिनका मूलधन और जिन पर ब्याज केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया और बिना किसी शर्त के प्रत्याभूत हो;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित ऋण म्यूचुअल फंडों की यूनितें;
- (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथापरिभाषित किसी बैंक और किसी सरकारी वित्तीय संस्थान सहित किसी निकाय कारपोरेट द्वारा निर्गमित सूचीबद्ध (या नए निर्गमन के मामले में एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियां, जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि निवेश की तारीख से तीन वर्ष हो;
- (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अधीन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गमित बेसल III श्रेणी-I बांड जो या तो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हों;

(च) अवसंरचना संबंधी सूचीबद्ध या नए मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित निम्न ऋण लिखतें:—

- (i) अवसंरचना के विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा कम लागत वाले आवासों के विकास, निर्माण या वित्तपोषण के व्यवसाय में मुख्य रूप से लगे हुए किसी निकाय कारपोरेट द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियां;
 - (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में प्रचालनरत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी अवसंरचना ऋण निधि द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां; या
 - (iii) किसी म्यूचुअल फंड के रूप में प्रचालनरत और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित किसी अवसंरचना ऋण निधि द्वारा निर्गमित यूनितें;
- (छ) किसी मान्यताप्राप्त ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें निवेश की तारीख को बाजार पूंजीकरण पांच हजार करोड़ रुपए से कम न हो, सूचीबद्ध निकाय कारपोरेट के शेयर;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों के ऐसे यूनित जिन्होंने मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध निकाय कारपोरेट के शेयरों में अपना न्यूनतम पैसठ प्रतिशत निवेश किया हो, या
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों या इंडेक्स फंडों जिनकी प्रतिकृति बंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडेक्स में, या किसी निकाय कारपोरेट में भारत सरकार की शेयरधारिता के निवेश के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित इंडेक्स के पोर्टफोलियों में हो;

बशर्ते कि खंड (घ), (ड.) और (च) के अधधीन निवेश ऐसी ही प्रतिभूतियों में किया जाएगा जिनका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण पात्रता निर्धारण अभिकरण) विनियमन, 1999 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में पंजीकृत कम से कम दो ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों से अनुप्रयोज्य पात्रता निर्धारण मान में न्यूनतम श्रेणी निर्धारण एए या समकक्ष हो:

बशर्ते यह भी कि खंड (च) के उप-खंड (ii) के तहत निवेश के मामले में, पात्रता निर्धारण का संबंध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से होगा और उस उपखंड में पात्रता निर्धारण का संबंध निधि की स्कीम के निवेश ग्रेड से ऊपर के लिए निर्धारित पात्र प्रतिभूतियों में निवेश से होगा:

बशर्ते यह भी कि यदि प्रतिभूतियों या कंपनियों का पात्रता निर्धारण दो से अधिक एजेंसियों द्वारा किया गया हो तो, सभी पात्रता निर्धारणों में से दो निम्नतम निर्धारणों पर विचार किया जाएगा।

[फा. सं. 6/5/सीएम/2002-वॉल्यूम V]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O. 1267(E).—In pursuance of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Central Government hereby specifies the following securities for the purposes of the said section, namely:—

- (a) Government securities;
- (b) securities, the principal whereof and the interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government;
- (c) units of debt mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India established by section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

- (d) listed (or proposed to be listed on exchanges in case of fresh issue) debt securities issued by any body corporate, including a bank and a public financial institution as defined in clause (72) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), which have a minimum residual maturity period of three years from the date of investment;
- (e) Basel III Tier-I bonds issued by a scheduled commercial bank under guidelines issued by the Reserve Bank of India, which are either listed or are proposed to be listed on an exchange;
- (f) the infrastructure related debt instruments listed or proposed to be listed in case of fresh issue:—
 - (i) debt securities issued by a body corporate engaged mainly in the business of development or operation and maintenance of infrastructure, or development, construction or finance of low cost housing;
 - (ii) securities issued by an infrastructure debt fund operating as a non-banking financial company and regulated by the Reserve Bank of India; or
 - (iii) units issued by an infrastructure Debt Fund operating as a Mutual Fund and regulated by the Securities and Exchange Board of India;
- (g) shares of body corporates listed on any recognised stock exchange which has a market capitalisation of not less than five thousand crore rupees as on the date of investment;
- (h) units of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India, which have minimum sixty-five per cent of their investment in shares of body corporates listed on a recognised stock exchanges; or
- (i) exchange traded funds or index funds regulated by the Securities and Exchange Board of India which replicate the portfolio of the Bombay Stock Exchange Sensex Index or the National Stock Exchange Nifty Index, or those constructed specifically for disinvestment of shareholding of the Government of India in a body corporate:

Provided that the investment under clauses (d), (e) and (f) shall be made only in such securities which have minimum AA rating or equivalent in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered with the Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agency) Regulations, 1999:

Provided further that in case of investment under sub-clause (ii) of clause (f), the ratings shall relate to the non-banking financial company and for that sub-clause, the ratings shall relate to the investment in eligible securities rated above investment grade of the scheme of the fund:

Provided also that if the securities or entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of all the ratings shall be considered.

[F. No. 6/5/CM/2002-Vol.V]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy.